

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 625 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 नवम्बर 2017—अग्रहायण 1, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2017

क्र. एफ बी-04-12-2016-2-पांच(32).— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम मण्डल, भोपाल द्वारा 01 अक्टूबर, 2017 से 31 मार्च 2019 की समयावधि के दौरान जारी की गयी बीमा पॉलिसी पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क निम्न शर्तों पर समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. ऐसी प्रत्येक पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान उपर्युक्त रीति से कर दिया गया है, ऐसा पृष्ठांकन केवल इस अधिनियम के अधीन की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की राशि की सीमा तक किए जा सकेंगे.
2. वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में जमा की गई समेकित रकम रुपये 1.00 करोड़ (रुपए एक करोड़ मात्र) केवल के चालान की प्रति परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, भोपाल में प्रस्तुत की जाएगी.
3. उस अवधि के लिए शुल्क का समेकन किया गया है, समाप्त होने के तुरंत पश्चात्, वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बीमित राशि की पॉलिसी क्रमांक तथा पॉलिसियों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की सही रकम से मिलकर बने वाली विवरणी क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2017

क्र. एफ बी-04-12-2017-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-12-2016-2-पांच(32), दिनांक 22 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2017

No. B-4-12-2016-2-V-(32).—In exercise of the powers conferred by clause (b) sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, directs that the stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by Divisional Office, Life Insurance Corporation of India, Bhopal during the Period from 1st October 2017 to 31st March 2019 may be consolidated and paid into any government treasury of Madhya Pradesh on the following conditions, namely :—

1. It shall be indicated by endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.
2. A copy of the challan of payment of consolidation amount of Rs. 1.00 Crore (Rupees One Crore) only in any Government Treasury of Madhya Pradesh for the Financial Year 2017-18 and 2018-19 shall be submitted in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Bhopal.
3. Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the policy numbers of sum insured and the exact amount of stamp duty paid on the policies at the end of every quarter for the Financial Year 2017-18 and 2018-19 shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.